to save lives due to pesticide poisoning are as follows:

1. The Registration Committee set up under the Insecticides Act, 1968 registers pesticides only after evaluating their safety and efficacy.
2. The labels and leaflets which are mandatory part of the pesticides package provide information on usage, safety measures to be observed, first aid measures and anti-dote to be used in case of poisoning.
3. The Central and State Governments and manufacturers impart training to farmers, dealers and other users on various only aspects of pesticides safety and usage.
4. The Government is advocating the Integrated pest Management technology for pest control which envisages the use of biological, cultural, mechanical and other methods of pest control in addition to safe, judicious and need based application of pesticides.

(c) If pesticides are used as per the good Agricultural Practices pesticide residue should be within the prescribed levels.

(d) Yes, Sir. Under Section 26 of the Insecticides Act, 1968 most of the States/ Uts have notified the functionaries for collecting all the occurrences of pesticide poisoning coming within their cognizance. Pesticides residues in different food commodities are monitored under the prevention of Food Adulteration Act, 1954.

Statement

The number of pesticides poisoning death cases statewise during last 3 years.

s. N	Name of State/Ulk.	1990-91	1991-92	1992-93
1.	Andhra Pradesh	76	—	—
2.	Aiunachal Pradesh	—	—	—
3.	Assam	—	—	—
4.	Bihar	—	—	—
5.	Goa	—	—	—
6	Gujarat	34	—	143
7.	Haryana	76	70	53
8	Himachal Pradesh	4	—	—
9.	Jammu & Kashmir		—	—
10	Karnataka	23	—	—
11	Kerala	528	—	362
12.	Madhya Pradesh	1249	—	—
13.	Manipur	—	—	—
14.	Maharashtra	269	—	404*
15.	Meghalaya	—	—	—
16.	Mizoram	—	—	—
17.	Nagaland	—	—	—
18.	Orissa	—	—	—
19.	Punjab	—	40	—
20.	Rajasthan	284	39	116
21.	Sikkim	—	—	—
22.	Tamil Nadu	—	69	—
23.	Tripura	—	—	5* —
24.	Uttar Pradesh	33	1	—
25.	West Bengal	—	—	—
26.	Andaman	—	—	1* —
27.	Chandigarh	—	—	—
28.		—	—	—
29.	Daman & Diu	—	—	—
30	Delhi	—	—	41*
31.	Lakshadweep	—	—	—
31	Pondicherry	—	61	—

figure shown are for the period 1991—93.Noyear-wiaebreak up is available.

REMARKS: The figures have been compiled based on the information furnished by the State Authorities othrr at the Zonal Conferences *or* figures furnished to Government of India. Ministry of Agriculture, Deptt. of Agriculture and Cooperation, Die. of Plant Protection, Quarantine & Storage Faridabad

Export of Foodgrains

2485. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the availability of foodgrains in Government godowns is in abundance and therefore a decision has been taken to export the same; -

(b)if so, whether any assessment has been made in respect of profit or loss likely to be incurred from the export of wheat;

(c)if so, what are the details of the estimates made in this regard;

(d)whether Government would review the proposal regarding export of foodgrains in case the money earned through such export is likely to be less than the economic cost of Food Corporation of India;

(e)whether Government would chalk out a scheme to sell the surplus foodgrains through Public Distribution System in poor, backward and tribal regions of the country; and

(0 if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI): (a) to (d) At present stock of foodgrains in the Central Pool is very comfortable and to reduce the subsidy and to contain the market prices, the Government has decided to undertake open sale of wheat and rice during 1994-95 also. No decision has yet been taken to export wheat and rice from the Central Pool.

(e) and (f) Already a Revamped Public Distribution System (RPDS) is inoperation to distribute the foodgrains among poor, backward and tribal regions of the country at a specially subsidised rate and the Central Issue Price (Ex-FCI Godowns) is less by Rs. 50/per quintal than the rate prescribed for normal Public Distribution System.

चीनी का उत्पादन

2486. श्री दिलीप सिंह जूदेव:
श्री जनार्दन यादव:

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1990, 1991, 1992 और 1993 में अब तक देश में राज्य-वार चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या चीनी का उत्पादन इसके लक्ष्य से कम हुआ है;

(ग) यदि हां, तो कितना कम हुआ है;

(घ) केन्द्रीय पूल में राज्य-वार कितनी चीनी उपलब्ध कराई गई;

(ङ) इस वर्ष कितनी चीनी का निर्यात किये जाने का विचार है; और

(च) चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय): (क) अपेक्षित सूचना विवरण पर है। (नीचे देखिए)

(ख) और (ग) चीनी उत्पादन के कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जा रहे हैं। तथापि, आठवीं पंचवर्षीय योजना में चीनी उद्योग की विकास कार्यक्रम के लिए गठित की गई समिति ने पूरे भारत में 1992-93 मौसम के लिए चीनी उत्पादन का लक्ष्य 121.68 लाख टन और 1993-94 मौसम के लिए 127.76 लाख टन निर्धारित किया है। 1992-93 चीनी मौसम के दौरान कुल उत्पादन 106.09 लाख टन था। चालू चीनी मौसम 1993-94 में चीनी उत्पादन की वर्तमान प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि पूरे मौसम के दौरान वास्तविक उत्पादन इस मौसम के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य से बहुत कम होगा।

(घ) 17.12.1979 से चल रही आंशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति के तहत प्रत्येक चीनी फैक्ट्री के कुल उत्पादन का विनिर्दिष्ट प्रतिशत (विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के तहत उच्चतर खुली बिक्री कोटे की पात्र फैक्टियों को छोड़कर) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए अधिसूचित एक्स-फैक्ट्री लेवी कीमतों पर लेवी चीनी के रूप में रिलीज किया जाता है। 1992-93 से लेवी-खुली बिक्री के कोटे का अनुपात 40:60 है। लेवी चीनी के वितरण के लिए अलग से कोई केन्द्रीय पूल नहीं बनाया गया है।

(ङ) यू.एस.ए./ई.ई.सी. को तरजीही कोटा और भारत-नेपाल व्यापार संधि के अंतर्गत नेपाल को अपेक्षित मात्रा के सिवाय वर्तमान वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान चीनी निर्यात का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) सरकार ने 1993-94 चीनी मौसम के दौरान चीनी उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

(1) 1.10.1993 से 15.11.1993 तक की अवधि के दौरान किए गए उत्पादन पर चीनी मिलों को 60 प्रतिशत की सामान्य पात्रता की तुलना में 72 प्रतिशत की दर से उच्चतर खुली बिक्री कोटे के रूप में जल्दी पेराई प्रोत्साहनों की घोषणा की गई थी।

(2) 1.1.1994 से 30.9.1994 तक की अवधि के दौरान चीनी मिलों को 1992-93 मौसम की इसी अवधि में किए गए उत्पादन से अधिक अतिरिक्त/इंक्रीमेंटल चीनी उत्पादन पर 60 प्रतिशत की सामान्य पात्रता की तुलना में 80 प्रतिशत की दर से उच्चतर खुली बिक्री कोटे के रूप में बीच की पेराई के लिए प्रोत्साहनों की घोषणा की गई थी।

(3) 1.5.1994 से 31.7.1994 तक की अवधि के दौरान किए गए चीनी उत्पादन पर चीनी मिलों को 60 प्रतिशत की सामान्य पात्रता की तुलना में 72 प्रतिशत की दर से उच्चतर खुली बिक्री कोटे के रूप में देर तक पेराई प्रोत्साहन प्रदान करने की घोषणा की गई थी।

(4) 1.8.1994 से 30.9.1994 तक की अवधि के लिए चीनी मिलों को 1992-93 मौसम की इसी अवधि में किए गए उत्पादन से अतिरिक्त/इंक्रीमेंटल उत्पादन पर 60 प्रतिशत की सामान्य पात्रता की तुलना में 100 प्रतिशत की दर से उच्चतर खुली बिक्री कोटे के रूप में प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है।